



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 154(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक के परामर्श से, केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों के पक्ष में आयु सीमा को शिथिल करने का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर निवासी (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट) नियम, 2018 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. लागू होना--

ये नियम सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों को लागू होंगे, जिनकी भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या अन्यथा के माध्यम से की जाती है।

3. ऊपरी आयु सीमा में छूट--

जब भी नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों के लिए भर्ती की जाती है, उन सभी व्यक्तियों को, जो साधारणतया जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 के बीच अधिवास कर रहे थे, ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुज्ञेय होगी :

परंतु किसी परीक्षा में भाग लेने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम अवसरों की संख्या की शर्त के अधीन होगी।

4. निवास के सबूत के संबंध में प्रमाणपत्र—

नियम 3 के अधीन अनुज्ञेय आयुसीमा में छूट का लाभ लेने की वांछा रखने वाला व्यक्ति निम्नलिखित से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में अधिवास कर रहा था—

- (क) जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अधिकारिता में वह साधारणतया निवास कर रहा था ; या
- (ख) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित कोई अन्य प्राधिकारी ।

5. निर्वचन—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

6. भर्ती नियमों का संशोधन—

केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों, जिसके अंतर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पद हैं, में व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम और उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शासन करने वाले नियम, इन नियमों में उपबंधित सीमा तक संशोधित हो गए समझे जाएंगे ।

7. निर्बंधन—

ये नियम 31 दिसंबर, 2019 तक प्रवृत्त रहेंगे और उक्त अवधि के परे कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. 15012/1/2014-स्था. (घ)]

जानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने उन सभी व्यक्तियों को, जो 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में साधारणतया अधिवास कर रहे थे, 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए आयु सीमा में छूट देने का विनिश्चय किया है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2018

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules regulating the relaxation of age limit in favour of the Residents of the State of Jammu and Kashmir for appointment to Central Civil Services and Posts, namely:—

1. Short title and commencement .-

- (1) These rules may be called the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 2018.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2018.

2. Application .-

These rules shall apply to all Central Civil Services and Posts recruitment to which are made through the Union Public Service Commission or the Staff Selection Commission or otherwise by the Central Government.

3. Relaxation of upper age limit .-

Wherever any recruitment to the services and posts referred to in rule 2 is made, a relaxation in the upper age limit of five years shall be admissible to all persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989;

Provided that the relaxation in the upper age limit for appearing at any examination shall be subject to the maximum number of chances permissible under the relevant rules.

4. Certificate regarding proof of residence .-

Any person intending to avail of the relaxation of age-limit admissible under rule 3 shall submit a certificate from –

- (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he had ordinarily resided; or
- (b) any other authority designated in this behalf by the Government of Jammu and Kashmir,

to the effect that he had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

5. Interpretation .-

If any question arises as to the interpretation of these rules, the same shall be decided by the Central Government.

6. Amendment of recruitment rules .-

All rules regulating the recruitment of persons to Central Civil Services and Posts including those in the Indian Audit and Accounts Department and the rules governing competitive Examinations therefor shall be deemed to have been amended to the extent provided for in these rules.

7. Limitation .-

These rules shall remain in force till the 31st day of December, 2019 and there shall be no further extension beyond the said period.

[F. No. 15012/1/2014-Estt.(D)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to extend the age relaxation to all persons who had ordinarily been domiciled in the State of Jammu and Kashmir during the period from the 1st day of January, 1980 to the 31st day of December, 1989 for a period of two years to be effective from the 1st January, 2018.

It is clarified that the interest of no person shall be adversely affected by issuing these rules with retrospective effect.